

सिरसा नदी प्रदूषण मामले में एनजीटी ने दिखाई सख्ती

हिमाचल-हरियाणा को नोटिस, रोपड़ में सतलुज पर असर की जांच होगी, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को

समर न्यूज़। रोपड़

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश की सिरसा नदी में कथित प्रदूषण और उसके पंजाब के रोपड़ क्षेत्र में सतलुज पर पड़ रहे असर का संज्ञान लिया है। अधिकरण ने मामले को पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यह कार्रवाई रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा की ओर से दायर आवेदन पर हुई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने 9 सितंबर को



मामले की सुनवाई की। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल के बड़ी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट नालों और जलधाराओं के जरिये सिरसा नदी में पहुंच रहा है। आगे यह नदी सतलुज में मिलती है, जिससे रोपड़ क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता प्रभावित

होने की आशंका जताई गई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के नमूना परीक्षण में घनीली के पास सिरसा नदी की स्थिति चिंताजनक पाई गई।

मार्च 2026 में कुल कोलीफॉर्म 60,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कोलीफॉर्म 17,000 एमपीएन प्रति 100

एफआईआर के बाद एनजीटी तक मामला
इससे पहले रोपड़ में सतलुज के हेडवर्क्स के पास औद्योगिक कचरा और अन्य सदिग्ध सामग्री जमा होने के बाद अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने नमूने लिए और स्रोत का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के संबंधित क्षेत्रों तक जांच का मुद्दा उठाया था। एनजीटी ने संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले सेवा-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब निगाह इस बात पर है कि जांच में प्रदूषण के वास्तविक स्रोत, उपचार व्यवस्था और सतलुज तक पहुंच रहे प्रदूषण की गिननेवारी किसकी तय होती है।

मिलीलीटर तक पहुंच गया। निर्धारित मानक की तुलना में फीकल कोलीफॉर्म का स्तर करीब 34 गुना अधिक था। दिसंबर 2025 में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी 15 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंची थी।
■ **उद्योग और सीवेज पर उठे सवाल** – विधायक ने दावा किया है कि बड़ी क्षेत्र में करीब 2,200

उद्योग हैं, जिनमें लगभग 1,000 इकाइयां तरल अपशिष्ट पैदा करती हैं, जबकि करीब 377 इकाइयों का अपशिष्ट साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र तक पहुंचता है। उन्होंने घरेलू सीवेज के अपर्याप्त उपचार का मुद्दा भी उठाया है। हालांकि, इन दावों की जिम्मेदारी और वास्तविक स्रोत की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

फरीदकोट में 12 किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

■ तरनतारन से बाइक पर सफ़ाई देने आए थे, नाके पर पुलिस ने दबोचा
समर न्यूज़। फरीदकोट

फरीदकोट पुलिस के सीआईए स्टाफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 किलो 221 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ सदर थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरनतारन जिले के गांव करमूवाला निवासी सुदागर सिंह उर्फ घुल्ला और कवलजीत खान उर्फ कम्मू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों बाइक से हेरोइन की खेप लेकर फरीदकोट में

सफ़ाई देने पहुंचे थे। सीआईए प्रभारी उपनिरीक्षक हक़म सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार रात अमृतसर-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग-54 पर गांव चंदबाजा के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान तलवंडी भाई की ओर से बाइक पर आ रहे दोनों युवकों ने पुलिस को देखकर वापस भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को मौके पर पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान कवलजीत के कंधे पर लटके किट बैग से छह पैकेट बरामद हुए। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में जांच कराई, जिसमें सभी पैकेटों में हेरोइन मिली। बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन 12 किलो 221 ग्राम बताया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।

जातीय समीकरण पर भिड़ी आप और भाजपा

समर न्यूज़ | चंडीगढ़
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव जातीय समीकरणों तक पहुंचता दिख रहा है। आप ने भाजपा पर जातीय पहचान को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि पंजाब की राजनीति में विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन और सामाजिक भाईचारे महत्वपूर्ण रहा है।

ऐसे में जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश सामाजिक ताने-बाने के लिए उचित नहीं होगी। भाजपा पंजाब में अपनी पुरानी शहरी हिंदू मतदाता वाली छवि से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी की गतिविधियां दलित, पिछड़े, किसान और युवा वर्गों तक भी बढ़ी हैं।

भोला ड्रग मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी को जमानत नहीं

चार साल छह महीने की हिरासत के बावजूद याचिका खारिज
समर न्यूज़। चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भोला ड्रग सिंडिकेट मामले में बर्खास्त पंजाब पुलिस उपनिरीक्षक सरबजीत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह देओल की खंडपीठ ने मुकदमे की सुनवाई को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि जब बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से 10 गुना से अधिक हो, तो सुनवाई में तेजी जरूरी है। राज्य के अनुसार सरबजीत सिंह पर जगदीश सिंह उर्फ भोला और अन्य आरोपियों से जुड़े संगठित मादक पदार्थ तस्करी गिरोह को मदद पहुंचाने का आरोप है। जांच में आरोप लगाया गया कि उसने पुलिस की वर्दी पहनकर

नशीले पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को नाकों और जांच चौकियों से बिना रोक-टोक निकलवाने में मदद की। मामले में उसे 9 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अदालत ने माना कि आरोपी करीब चार साल छह महीने से हिरासत में है, लेकिन अपराध की गंभीरता, बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और पुलिस पद के कथित दुरुपयोग को देखते हुए इस आधार पर फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन देरी जमानत का अकेला आधार नहीं हो सकती। यदि जमानत पर मौजूद कोई सह-आरोपी सुनवाई में जानबूझकर देरी करता है तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसकी जमानत रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है।

पंजाब में पुलिस-गैंग्स्टरों का गठजोड़ : रंधावा

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर गैंग्स्टरों से कथित साठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल फोन तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।

रंधावा ने कहा कि इससे अधिकारियों के संपर्कों और बातचीत की वास्तविकता सामने आ सकती है। रंधावा ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सीमा क्षेत्र में तैनात और वहां से स्थानांतरित किए गए कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी की। उन्होंने डेरा बाबा नानक और बटाला से तबादला किए गए पुलिस उपाधीक्षकों को लेकर सवाल उठाए। रंधावा ने आरोप लगाया कि गैंग्स्टरों का प्रभाव बढ़ रहा है और कुछ मामलों में जेल से नेटवर्क संचालित किया जा रहा है।

पंजाब में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराया

■ तीन थर्मल यूनिट बंद, मांग बढ़ने से दिन-रात बिजली कटों ने बढ़ाई परेशानी

समर न्यूज़। चंडीगढ़

पंजाब में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। राज्य के दो निजी और एक सरकारी थर्मल प्लांट की एक-एक यूनिट बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। बिजली की मांग और उपलब्ध उत्पादन के बीच अंतर बढ़ने के कारण कई इलाकों में दिन-रात कट लगाए जा रहे हैं।

तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की तीन में से एक यूनिट पहले से बंद है। इसके बाद गुरुवार देर रात राजपुरा थर्मल प्लांट की भी एक यूनिट बंद हो गई। वहीं एक सरकारी थर्मल प्लांट की यूनिट में भी बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। इससे राज्य की कुल बिजली उपलब्धता पर असर पड़ा है। उत्पादन कम होने के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन



लिमिटेड (पीएसपीसीएल) केंद्रीय बिजली पूल से अतिरिक्त बिजली खरीद रहा है। इसके बावजूद मांग अधिक होने के कारण आपूर्ति बनाए रखने में मुश्किल आ रही है। कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अधोषित कटों का सामना करना पड़ रहा है।

पर्याप्त नहीं कोयले की आपूर्ति: बिजली की कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि थर्मल प्लांटों में कोयले का भंडार कम है और पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलने पर बिजली संकट पैदा हो सकता है। पीएसपीसीएल के अधिकारियों के अनुसार कोयले की आपूर्ति जारी है, लेकिन जरूरत के मुकाबले कम होने से थर्मल प्लांट पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।

जालंधर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दफ्तर का मुख्य गेट बंद किए जाने और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार कर बंद गेट को फांदकर डीसी दफ्तर के भीतर जाने की कोशिश की।

पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को गेट के पास ही रोक दिया। इससे कुछ समय के लिए प्रदर्शन स्थल पर हंगामे की स्थिति बनी रही। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की।

सीएम सैनी बोले- तस्करों पर कार्रवाई का असर जमीन पर भी दिखना चाहिए

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा

■ बोले- सिर्फ दावे नहीं, नतीजे भी सामने आने चाहिए, सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा
समर न्यूज़। चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथन सिंह सैनी ने पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ अभियान और इसके परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल कार्रवाई के आंकड़े बताने से समस्या खत्म नहीं होगी। नशा तस्करी पर प्रभावी रोक के लिए तस्करों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालना जरूरी है। उनका यह बयान पंजाब में नशे को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के बीच आया है।

सैनी ने पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उन्होंने संकेत दिया कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई केवल छोटे स्तर के आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे तंत्र को निशाना बनाया जाएगा। उनका यह रुख भाजपा के उस व्यापक अभियान से जुड़ा है, जिसमें पंजाब में नशे को अगामी विधानसभा



चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है।
■ **आंकड़ों पर आमने-सामने:** पंजाब सरकार लगातार नशा तस्करी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का दावा कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुप्त सूचनाओं के आधार पर हजारों मामले दर्ज किए गए हैं और बड़ी संख्या

■ **चुनावी मुद्दा बना नशा**
सैनी के बयान से स्पष्ट है कि भाजपा पंजाब में नशे के सवाल को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज की कसौटी के रूप में पेश करने की तैयारी में है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। आप सरकार के लिए चुनौती अब कार्रवाई के आंकड़ों के साथ जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाने की भी है।

में गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार का कहना है कि नशे की आपूर्ति रोकने के साथ पुनर्वास और जागरूकता पर भी काम किया जा रहा है। विपक्ष इन दावों के बावजूद पंजाब के गांवों में नशे की उपलब्धता और इससे प्रभावित परिवारों की स्थिति को मुद्दा बना रहा है। हाल की घटनाओं ने इस बहस को और तीव्र किया है। संगठन में एक व्यक्ति की मौत के बाद नशे के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग तेज हुई है।

मोदी के जन्मदिन से सेवा संकल्प अभियान, सीएम योगी ने दिए निर्देश

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान; 12 तरह की सेवा गतिविधियां होगी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर रात कार्यकर्ताओं को वचुंअल माध्यम से जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए।

अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अधिकतम भागीदारी पर जोर: मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अभियान के तहत निर्धारित सभी गतिविधियों को पूरी सक्रियता के साथ आयोजित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि सेवा कार्यों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी

योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास हो। एक महीने के अभियान के दौरान कुल 12 प्रकार की सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वचुंअल बैठक में कार्यकर्ताओं को अभियान की रूपरेखा, गतिविधियों के आयोजन और संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई।

योगी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। सेवा कार्यों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और जनसेवा की भावना को मजबूत करने का प्रयास होना चाहिए। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मोहन यादव ने अक्षत के परिजनों से की बात

एजेंसी। भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में हादसे में जान गंवाने वाले कटनी निवासी अक्षत यादव के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से अक्षत के पिता मंतू सिंह यादव और अन्य परिजनों से बातचीत की। उन्होंने अक्षत के निधन पर गहरा दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षत के साथ हुई घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में वे स्वयं और पूरी मध्य प्रदेश सरकार परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ढाढस बंधाते हुए कहा कि परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति मिले, यही उनकी प्रार्थना है। 19 वर्षीय अक्षत यादव दिल्ली में रहकर दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। वह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे।

सुख्बू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक स्थगित

■ 11 सितंबर को प्रस्तावित बैठक अपरिहार्य कारणों से टली, नए आदेश तक नहीं होगी
समर न्यूज़। शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्बू की अध्यक्षता में 11 सितंबर को प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। बैठक को आगामी आदेशों तक टाल दिया गया है।

सरकार की ओर से इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना थी। हालांकि, बैठक स्थगित किए जाने के कारण

अब इन प्रस्तावों पर निर्णय के लिए नई तारीख का इंतजार करना होगा। सरकार की ओर से फिलहाल बैठक की नई तारीख घोषित नहीं की गई है। बैठक को स्थगित करने का फैसला अपरिहार्य कारणों से लिया गया है। नई तारीख तय होने के बाद इसकी जानकारी जारी की जाएगी।

मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लंबित प्रस्तावों के साथ नए विषय भी चर्चा के लिए शामिल किए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का प्रदेश के विभिन्न विभागों और प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ता है।

बैठक टलने के बाद जिन मामलों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी है, उन पर फिलहाल फैसला आगे बढ़ गया है। सरकार की ओर से अगली बैठक को लेकर आदेश जारी होने का इंतजार है।

हरिपुर को हरिद्वार जैसा केंद्र बनाने की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी। देहरादून

उत्तराखंड सरकार देहरादून के कालसी स्थित हरिपुर को हरिद्वार की तर्ज पर प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

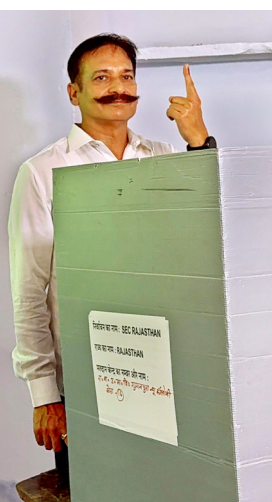
नवनिर्मित यमुना घाट का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा दिवस भी है। धार्मिक केंद्र के रूप में विकास: सरकार की योजना केवल घाट निर्माण तक सीमित नहीं है। हरिपुर को यमुना के मैदानी क्षेत्र में बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए धार्मिक स्थलों और श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी : राजीव दत्ता

समर न्यूज़ | कोटा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विशेष कार्याधिकारी और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने शुक्रवार को मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने आम लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की।

राजीव दत्ता ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का वोट बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि नागरिक की जिम्मेदारी भी है। हर मतदाता को समय निकालकर



मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए और अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और

लंपी रोग पर भजनलाल सख्त टीकाकरण तेज करने के निर्देश

एजेंसी। जयपुर

राजस्थान में लंपी स्किन रोग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर रोग की स्थिति और नियंत्रण उपायों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभी रोग के मामले पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों तक सीमित हैं और पूरे प्रदेश में इसका प्रसार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को समय पर टीकाकरण, संक्रमित पशुओं को अलग रखने और रोग की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। टीकाकरण और दवाओं पर जोर: भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेज करने और प्रभावित क्षेत्रों में

रोग प्रतिरोधक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। गोशालाओं और अन्य स्थानों पर संक्रमित पशुओं को अलग रखने के साथ पशुपालकों को बीमारी के लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक 10,403 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 6,905 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 87 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण पूरा होने की जानकारी दी गई।

रोग नियंत्रण के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष तथा जिला और ब्लॉक स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और पशुपालकों को सावधानियां बरतने के लिए जागरूक करने को कहा।

फाइव-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल, हिमाचल में धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में प्रदर्शन

बैंक कर्मचारियों ने निकाली रैली, सरकार से लंबित मांगों जल्द पूरी करने की मांग; मांगें नहीं मानी तो सितंबर में दोबारा हड़ताल, 26 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी

समर न्यूज़ | हमीरपुर/धर्मशाला/ऊना

बैंक कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी एकदिवसीय सांकेतिक हड़ताल का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। हमीरपुर, धर्मशाला और ऊना में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर रैली निकालकर केंद्र सरकार व बैंक प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया।



का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद 11वें और 12वें द्विपक्षीय समझौते होने के बावजूद यह मांग पूरी नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2024 में भी पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव और सहमति बनी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया।

कर्मचारियों ने कहा कि यदि सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाती है तो वे कार्यदिवसों में प्रतिदिन अतिरिक्त समय देकर इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक, शेयर बाजार और सेबी सहित कई वित्तीय संस्थानों में पांच दिन कार्य व्यवस्था लागू है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी सप्ताह में छह दिन काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वित्त मंत्रालय सिफारिश कर चुका है, लेकिन सरकार की ओर से मामले को लगातार टाला जा रहा है।

कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 2015 में 10वें द्विपक्षीय समझौते के दौरान पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग रखी गई थी। उस समय दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश लागू करने के साथ भविष्य में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने

इंसेंटिव में समानता की मांग

बैंक कर्मचारियों ने परफॉर्मेंस लिंकड इंसेंटिव में भी समानता की मांग उठाई है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि बैंक के प्रदर्शन और लाभ में योगदान देने वाले निचले स्तर के कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के बीच इंसेंटिव में काफी अंतर है। हमीरपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सर्फिल सचिव अजय कतना ने कहा कि यूनियन की मांग है कि बैंक के प्रदर्शन और लाभ के आधार पर कर्मचारियों को पांच से 15 दिनों तक का इंसेंटिव दिया जाए। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में फीलड पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव व्यवस्था में समानता लाई जानी चाहिए। धर्मशाला में हिमाचल बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन एवं पीएनबी स्टाफ यूनियन हिमाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार गौतम ने भी इंसेंटिव व्यवस्था में असमानता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने में क्लर्क, पीएन और स्केल-1 से 3 तक के कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है, इसलिए इंसेंटिव में उनके योगदान को उचित महत्व मिलना चाहिए।

वर्कफोर्स को लेकर भी उठाई आवाज

ऊना में बैंक कर्मचारियों ने वर्कफोर्स को स्केल-1 से स्केल-3 तक एक साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई। कर्मचारियों का कहना है कि कार्यभार और कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्कफोर्स का उचित विभाजन किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और बैंकिंग सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

बैंक कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो सितंबर में दोबारा आंदोलन किया जाएगा। संगठनों के अनुसार 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नोटबंदी और कोरोना महामारी जैसे मुश्किल दौर में भी बैंक कर्मचारियों ने लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग

बैंक कर्मचारी संगठनों ने वर्ष 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही लंबे समय पहले सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की मांग की गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ऐसे कई पेंशनर हैं, जिनकी मूल पेंशन पुरानी वेटन संरचना के आधार पर निर्धारित हुई थी। उनकी पेंशन को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।

नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को लॉटरी और भांग की खेती का तोहफा : त्रिलोक



सुभाष | विलासपुर
समर न्यूज़

सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी को बढ़ावा देने और भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन निर्णयों को प्रदेश और युवाओं के भविष्य के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि एक ओर हजारों युवा रोजगार और सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं सरकार उन्हें रोजगार के बजाय लॉटरी और भांग की खेती का विकल्प दे रही है। त्रिलोक जमवाल ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार नई नौकरियां पैदा करने के साथ-साथ लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करेगी, लेकिन सरकार की

प्राथमिकताएं इसके विपरीत दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी को बढ़ावा देने से युवाओं और समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। वहीं, भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने के फैसले पर भी सरकार को व्यापक स्तर पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली सरकार को ऐसे फैसलों के संभावित प्रभावों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भाजपा विधायक ने सरकार से मांग की कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर प्राथमिकता से काम किया जाए। उन्होंने खाली पड़े पदों को जल्द भरने और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करने की मांग की। जमवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में है और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

गुटबाजी से विचलित हैं सीएम, हार की हताशा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही : जयराम

■ पूछा- क्या 'नॉर्मल रूटीन' काम के लिए लोकतंत्र की धजियां उड़ार रहे थे?



समर न्यूज़ | शिमला

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी व वर्तमान राजनीतिक हालात को विचलित हैं और हार की हताशा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया में इसे 'नॉर्मल रूटीन' बताने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इतने 'नॉर्मल रूटीन' काम के लिए लोकतंत्र की धजियां उड़ा रहे थे? संविधान की मर्यादा तार-तार कर रहे थे? बार-बार पंचायती राज के चुनाव को रोकने की साजिश कर रहे थे? डिजान्स्टर एक्ट

का बहाना ले रहे थे? आपदा प्रभावितों के बीच अपने आपदा राहत के पैसे से सरकार के कार्यकाल का जश्न मना रहे थे। रोज नए-नए नियम बनाकर मित्र मंडल और उनके सहयोगियों, करीबियों को जनप्रतिनिधि बनाने का रास्ता साफ कर रहे थे, जिसे माननीय न्यायालय की ओर से बार-बार खारिज किया जा रहा था।

क्या 'नॉर्मल रूटीन' के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों और नेताओं के खिलाफ मुकदमें करके लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रहे थे? जयराम ठाकुर ने कहा कि क्या 'नॉर्मल रूटीन'

काम के लिए सरकार ने बार-बार न्यायालय की लताड़ खाकर अपनी फजीहत करवाई? इतने 'नॉर्मल रूटीन' के काम के लिए सत्ता के दुरुपयोग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या 'नॉर्मल रूटीन' के काम के लिए मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों को जिला पंचायत सदस्यों को प्रताड़ित करने के लिए लगा दिया था? ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या नॉर्मल रूटीन के लिए नियम-कानून और संविधान ताक पर रखने वाले सीएम हैं सुक्खू? हार की हताशा में मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं।

इससे पहले वह जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की वैल्यू को 'एक दिन' का बताकर जनादेश और माननीय न्यायालय पर टिप्पणी करके अपनी लोकतंत्र और संविधान विरोधी विचार सामने ला चुके हैं। मुख्यमंत्री को सच स्वीकार लेना चाहिए।

समर न्यूज़ | चंबा

चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत सेईकोटी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक मृत व्यक्ति के नाम पर आवास स्वीकृत किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सनवाल के मकन गांव के मान सिंह पुत्र कर्म चंद ने निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को शिकायत भेजकर विभागीय जांच, सरकारी धन की वसूली व दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेईकोटी पंचायत के गांव ओहला में पीएमएवाई-जी के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2018-19 में करीब 173 मकानों की सूची तैयार हुई थी। मामले का सबसे गंभीर पहलू पीएमएवाई-

जी के ऑनलाइन रिकॉर्ड और मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर सामने आया है। पीएमएवाई-जी के पोर्टल पर आरोप है कि तत्कालीन पंचायत सचिव की अनुशंसा पर प्रशासनिक अधिकारी ने 173 मकानों को स्वीकृति प्रदान की। लाभार्थी आईडी एचपी 115031476 के तहत लाभार्थी का नाम भागी, पिता का नाम दसराम, ग्राम नरवाड़, पंचायत सेईकोटी, विकास खंड तीसा दर्ज है। दूसरी ओर, मृत्यु प्रमाणपत्र में इसी नाम से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु 12 मार्च, 2024 दर्ज है। प्रमाणपत्र में ग्राम पंचायत सेईकोटी का उल्लेख है और पंजीकरण संख्या डी-2020, 2.00056-000007 दर्ज है।

उधर, खंड विकास अधिकारी तीसा गोपाल ठाकुर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करवाई जाएगी। जांच में तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

टीजीटी आर्ट्स के 414 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दे सरकार : एसएफआई

समर न्यूज़ | शिमला

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने हिमाचल प्रदेश सरकार से टीजीटी आर्ट्स भर्ती प्रक्रिया में चयनित 414 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति में हो रही देरी से अभ्यर्थियों में निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर और राज्य सचिव सनी सेकटा ने कहा कि टीजीटी आर्ट्स के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2026 में शुरू की गई थी और



इसमें 414 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बावजूद चयनित उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उन्होंने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की। एसएफआई नेताओं के अनुसार प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में देरी से एक ओर

शिमला जिला परिषद चुनाव में हार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया निराशाजनक समीक्षा की जरूरत, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से संगठन व सरकार पर हुई चर्चा

संजु | शिमला
समर न्यूज़

शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चुनाव परिणामों को कांग्रेस के लिए निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत दुर्ग रहा है, लेकिन पंचायतीराज चुनाव में पार्टी को उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। ऐसे में इन नतीजों की गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला जिले में

कांग्रेस की मजबूत लीडरशिप रही है। खासतौर पर जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से सभी जिला परिषद सदस्य जीतकर आए हैं, लेकिन जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी को अपेक्षा और आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। इसी कारण कांग्रेस जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पार्टी को यह स्वीकार करना होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में कमी रही और किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। इस पूरे मामले पर गंभीरता से मंथन किया जाएगा और पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा



कि इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगभग एक वर्ष का समय शेष है और ऐसे में पार्टी हित में मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला परिषद चुनाव के परिणामों को कांग्रेस स्वीकार करती है और अब यह देखना जरूरी है कि पार्टी से कहां कमी रह गई। कमियों को दूर कर संगठन को मजबूत किया जाएगा, ताकि आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। ठाकुर ने कहा कि उनका शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, जिसके चलते वह दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के दौरान पार्टी नेतृत्व से मुलाकात होना भी स्वाभाविक है।

बीपीएल चयन में पारदर्शिता पर पूरा जोर ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रही सरकार

राकेश | उना
समर न्यूज़

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर सीधा संवाद शुरू किया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने एसडीएम, खंड विकास अधिकारी केएल वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्लाट्टा, बरह, छपरोह समेत आठ पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों और विधायक ने ग्रामीणों तथा बीपीएल परिवारों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं

सुनीं और पात्रता व चयन प्रक्रिया की जानकारी दी। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बीपीएल चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के स्तर पर मिलकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जिससे चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

नूरपुर में नशा तस्कर की तीन करोड़ की संपत्ति जब्त, डेढ़ किलोग्राम से ज्यादा चरस पकड़ी थी

समर न्यूज़ | नूरपुर

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा है। पुलिस थाना डमटाल में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी बलविवंद उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद निवासी गांव छत्री इंदौरा जिला कांगड़ा की करीब 3.32 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।

सक्षम प्रहरीकी नई दिल्ली ने पुलिस द्वारा की गई वित्तीय जांच को सही मानते हुए संपत्ति की जम्ती की पुष्टि कर दी है। पुलिस के अनुसार 29 दिसंबर, 2025 को पुलिस थाना डमटाल में यह मामला एनडीपीएस

एक्ट की धारा 20 एवं 29 के तहत दर्ज हुआ था। कार्रवाई के दौरान आरोपी बलविवंद उर्फ बिल्ला के कब्जे से एक किलो 852 ग्राम चरस बरामद की गई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस जिला नूरपुर द्वारा आरोपी की चल एवं अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई।

पुलिस के मुताबिक जांच में ऐसी संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई, जिनका संबंध मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित आय से पाया गया। इसके आधार पर संबंधित अचल संपत्तियों, होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों तथा बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज यानी प्रतिबंधित किया गया। वित्तीय जांच के दौरान आरोपी की कुल संपत्ति का मूल्य 33232352.94 रुपए आंका गया था। पुलिस जिला नूरपुर ने पूरी वित्तीय जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को भेजी।

■ 17 मामलों में 30 करोड़ की संपत्ति जब्त: पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी और बरामदगी तक सीमित न रहते हुए उनकी अवैध कमाई और संपत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर, 2026 तक कुल 17 अभियोगों में आरोपियों की 299592857 रुपए की संपत्ति जब्त करवाई जा चुकी है।

जागरूकता

राकेश | उना
समर न्यूज़

ऊना में चिट्ठा और अन्य नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर 16 सितंबर को एंटी-चिट्ठा वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस महानिरीक्षक विमल गुप्ता ने शुक्रवार को ऊना के डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपयुक्त जितन लाल, बनगढ़ पुलिस बटालियन की कर्मांडेंट डॉ. आकृति शर्मा समेत



पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन और प्रतिभागियों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशे के खिलाफ सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। उन्होंने स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के

विद्यार्थियों, आईटीआई और कॉलेज छात्रों के साथ आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वॉकथॉन की शुरुआत सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी खेल मैदान से होगी। देशभर में पहचान बना चुका पुलिस बैंड 'हार्मनी ऑफ पाइन्स' अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम का आगाज करेगा। इसके बाद प्रतिभागी इंदिरा गांधी खेल मैदान से आईएसबीटी ऊना तक पैदल जाएंगे और वापस

खेल मैदान पहुंचकर वॉकथॉन का समापन होगा। प्रतिभागियों से सुबह 8 बजे तक आयोजन स्थल पर पहुंचने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुक्खू भी वॉकथॉन में शामिल होंगे। वह युवाओं से संवाद करने के साथ उनके साथ पैदल चलेंगे और नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रतिभागियों को नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाएंगे। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल और वॉकथॉन मार्ग पर छह पेयजल केंद्र बनाए जाएंगे। तीन स्थानों पर एंजुलेस की व्यवस्था रहेगी। प्रतिभागियों को आने और वापसी के दौरान रिफ्रेशमेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। क्यूआर कोड से पंजीकरण कराने वाले प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें एंटी-चिट्ठा थीम पर आधारित टी-शर्ट और कैप भी प्रदान की जाएंगी। विमल गुप्ता ने शैक्षणिक संस्थानों से विद्यार्थियों को अपने संस्थान के बैनर के साथ वॉकथॉन में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लकड़ी या तख्ते वाले बैनर न लाए जाएं, जिनसे किसी को चोट लगने का खतरा हो। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली बसों पर भी एंटी-चिट्ठा जागरूकता के बैनर लगाए जाएंगे, ताकि नशे के खिलाफ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

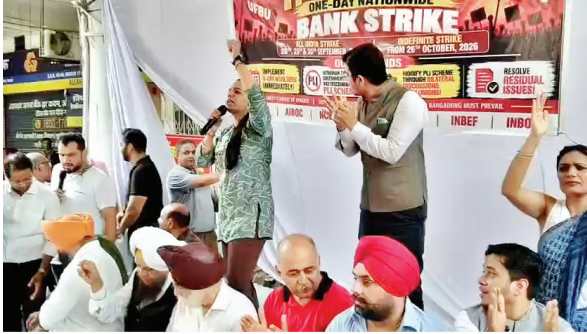
पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन

■ समझौते और बार-बार आश्वासन के बावजूद मांग लागू न होने से बड़ा रोष ■ 28 से 30 सितंबर को फिर हड़ताल, 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी दी चेतावनी

शगुन कश्यप | चंडीगढ़
समर न्यूज़

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण कई स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं और सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। चंडीगढ़ में बैंक स्वक्चार, सेक्टर-17 में विभिन्न बैंकों और यूएफबीयू से जुड़े कर्मचारी व अधिकारी एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि न्यायोचित मांगों पर औपचारिक समझौते और बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक अमल नहीं हुआ। इनमें सबसे प्रमुख मांग पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की है। नेताओं के अनुसार मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक यूनियनों के बीच इस संबंध में समझौता हुआ था, लेकिन ढाई साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया।



एक दिन का वेतन भी छोड़ा

हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों का उस दिन का वेतन काटा जाता है। यूनियन नेताओं ने कहा कि इसके बावजूद बैंककर्मियों ने सामूहिक मांग के समर्थन में एक दिन का वेतन त्यागकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे की गंभीरता और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। पांच दिवसीय बैंकिंग के अलावा यूएफबीयू ने एकतरफा और भेदभावपूर्ण पीएलआई व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई। यूनियनों ने मांग की कि पीएलआई में किसी भी बदलाव या उसके क्रियान्वयन से पहले यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाए। साथ ही बैंकिंग उद्योग से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों का भी समाधान किया जाए। स्थानीय प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि हड़ताल की सफलता ने बैंक कर्मचारियों की एकजुटता साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कोई अनुचित रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि पहले से हुए समझौते को लागू करने और लंबित मांगों का न्यायसंगत समाधान चाहते हैं।

आगे आंदोलन और तेज करने की तैयारी

यूएफबीयू कहा कि यदि सरकार और आईबीए की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सार्थक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके तहत 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को लगातार तीन दिन अखिल भारतीय हड़ताल तथा 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया गया है। नेताओं ने सरकार और आईबीए से अपील की कि औद्योगिक कार्रवाई को टालने के लिए तत्काल सार्थक वार्ता शुरू की जाए। प्रदर्शन में प्रियव्रत, इकबाल सिंह माल्ही, जगदीश राय, पंकज शर्मा, क्रांति राय, संतोष सिन्हा, गुर्वक्स सिंह, बीएस गिल, सचिन कटियार, अमनदीप, युगेश कुमार, विभोर, राजीव, अजय गैपुरिया, संजय महाजन, मुकेश, एसएस भाटिया, शोना हुडा, मंजु शर्मा, सुमन सांगवान, राजेश कौशल, ऋषि उपाध्याय, नरेंद्र कुमार, प्रेम पवार, विनय कुमार, गरुण शर्मा और आरएस वालिया सहित कई यूएफबीयू नेता मौजूद रहे।

वार्ड आरक्षण ने बदले निगम चुनाव के समीकरण 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व, 12 वार्डों में महिलाएं

ड्रॉ में वार्ड-29, 4, 9, 15, 1, 3 और 32 एससी के लिए आरक्षित

मोनिका रावत | चंडीगढ़
समर न्यूज़

नगर निगम चुनाव से पहले शुक्रवार को हुए वार्ड आरक्षण ड्रा ने शहर की राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं। वार्ड-29, 4, 9, 15, 1, 3 और 32 को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इनमें से तीन वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित होंगे, जबकि नौ वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

इस तरह कुल 12 वार्डों में महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। आरक्षण की नई तस्वीर सामने आने के बाद कई मौजूदा पार्षदों की राजनीतिक जमीन खिसक गई है और उन्हें अगले चुनाव के लिए दूसरे वार्डों में अपनी दावेदारी तलाशनी होगी।

इस बार आरक्षण का ड्रा पहले से आरक्षित 16 वार्डों को छोड़कर शेष 19 वार्डों में से किया गया। इन 19 वार्डों में से सात को एससी और नौ को सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना था। सात एससी वार्डों में से तीन एससी महिला के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार शेष 19 वार्डों में 16 वार्ड आरक्षित हो गए हैं और केवल तीन वार्ड ही अनारक्षित रहेंगे।

■ **कई मौजूदा पार्षदों के सामने वार्ड बदलने की चुनौती:** आरक्षण का सबसे बड़ा असर वार्ड-3 के भाजपा पार्षद दलीप शर्मा पर पड़ा है। लगातार चुनाव जीतने के बाद वह तीसरी बार अपने मौजूदा वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वार्ड के एससी के लिए

आरक्षित होने के बाद अब उन्हें नया राजनीतिक टिकाना तलाशना होगा। वार्ड-4 की भाजपा पार्षद और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा का चुनावी समीकरण भी बदल गया है। उनका मौजूदा वार्ड एससी के लिए आरक्षित होने के बाद अब उन्हें दूसरे वार्ड से टिकट की दावेदारी करनी होगी।

भाजपा पार्षद बिमला दुबे के लिए भी आरक्षण ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। वर्ष 2021 में वार्ड-7 एससी के लिए आरक्षित होने के कारण उन्होंने वार्ड-9 से चुनाव लड़ा था। अब वार्ड-9 भी एससी के लिए आरक्षित हो गया है, ऐसे में उन्हें एक बार फिर नई राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ेगी। वार्ड-15 के रामचंद्र यादव भी प्रभावित होने वाले नेताओं में शामिल हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यादव का वार्ड एससी के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दूसरे वार्ड की तलाश करनी होगी। वार्ड-29 के मुनवर का राजनीतिक भविष्य भी आरक्षण के बाद नए रिसे से तय होगा। आप की टिकट पर पार्षद बने मुनवर अब कांग्रेस में हैं। उनके वार्ड के एससी के लिए आरक्षित होने के बाद पार्टी को उनकी अगली चुनावी भूमिका पर नया फैसला करना होगा।

वार्ड-32 के भाजपा पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर जसमनजीत सिंह की सीट भी एससी के लिए आरक्षित हो गई है। उन्हें भी अगला चुनाव लड़ने के लिए दूसरे वार्ड से टिकट की संभावनाएं तलाशनी होंगी। वहीं वार्ड-1 में एससी आरक्षण के बाद

सामान्य वर्ग के मौजूदा दावेदारों के लिए चुनावी समीकरण बदल गए हैं।

■ **तीन एससी महिला और नौ सामान्य महिला वार्ड:** ड्रा के अनुसार सात एससी वार्डों में से तीन वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा नौ वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी कुल 12 वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। इसका सीधा असर उन पुरुष नेताओं पर पड़ेगा, जो लंबे समय से अपने-अपने वार्डों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। महिला आरक्षण वाले वार्डों में अब कई नेताओं को या तो दूसरे वार्डों का रुख करना होगा या फिर अपने परिवार से महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारना होगा। चंडीगढ़ में पूर्व में भी महिला आरक्षण के बाद कई नेताओं की पत्नियों और परिवार की अन्य महिला सदस्यों को मैदान में उतारने के उदाहरण सामने आ चुके हैं।

■ **अब शुरू होंगी टिकट की असली जंग:** आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों में टिकट की असली जंग शुरू होगी। जिन मौजूदा पार्षदों को वार्ड आरक्षित हो गए हैं, वे दूसरे वार्डों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं महिला आरक्षित वार्डों में नए महिला चेहरों की तलाश तेज होगी। आरक्षण ड्रा ने जहां कई मौजूदा पार्षदों के लिए वार्ड बदलने की मजबूरी पैदा कर दी है, वहीं नए नेताओं और महिला उम्मीदवारों के लिए निगम चुनाव में प्रवेश का रास्ता भी खोल दिया है।

पानी की समस्या लेकर नगर परिषद पहुंचे वार्ड आठ के लोग, जांच में अवैध निकले कनेक्शन

■ प्रधान ने दी राहत, बोले- कनेक्शन लीगल करवाएं, पानी की कमी नहीं आने देंगे : विर्क
गुरमीत सिंह | जीरकपुर
समर न्यूज़

नगर परिषद जीरकपुर के वार्ड नंबर 8 स्थित अंबेडकर कॉलोनी के निवासियों ने इलाके में पीने के पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

पार्षद निर्मला गौतम की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी मांग लेकर नगर परिषद अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह विरक के पास पहुंचे। हालांकि, मामले की जांच के दौरान एक चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि शिकायत लेकर पहुंचे लोगों में से



किसी के पास भी नगर परिषद का वैध पानी कनेक्शन नहीं था।

अंबेडकर कॉलोनी के निवासियों का कहना था कि पिछले कुछ समय से पानी की लाइन कट जाने के कारण उन्हें पीने के पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब लोग अपनी मांग लेकर प्रधान विरक के पास पहुंचे तो उन्होंने रिकॉर्ड और मौके की स्थिति की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि इलाके के

अधिकांश घरों ने नगर परिषद से आधिकारिक पानी कनेक्शन लिया ही नहीं था। नगर परिषद अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह विरक ने लोगों से कहा कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नियमों के तहत कनेक्शन लेना जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से अपने कनेक्शन जल्द से जल्द नगर परिषद के नियमों के अनुसार वैध करवाने और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने की अपील की।

क्रेस्ट के 75.4 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

■ तत्कालीन सीईओ आईएफएस नवनीत श्रीवास्तव और पत्नी समेत तीन आरोपित; 95 लाख की रकम से खरीदी गई संपत्ति
समर न्यूज़ | चंडीगढ़

चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) के 75.4 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में सीबीआई ने शुक्रवार को चंडीगढ़ की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच एजेंसी ने क्रेस्ट के तत्कालीन सीईओ और आईएफएस अधिकारी नवनीत श्रीवास्तव,

विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसकी निदेशक को आरोपित बनाया है। कंपनी को निदेशक नवनीत श्रीवास्तव की पत्नी है।

सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने समेत भ्रष्टाचार विनागर अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। जांच के अनुसार, क्रेस्ट के सीईओ पद पर रहते हुए नवनीत श्रीवास्तव ने अन्य आरोपितों के

साथ कथित साजिश रची और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खातों से क्रेस्ट के फंड का गबन किया। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने लोकसेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध आर्थिक लाभ हासिल किया। घोटाले की रकम में से 95 लाख रुपये उनकी पत्नी को मिले, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया।

इस मामले में सीबीआई नवनीत श्रीवास्तव को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वह न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी इससे पहले मामले में 13 अन्य आरोपितों

504 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ी जांच
क्रेस्ट का यह मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा में सामने आए बड़े बैंकिंग घोटाले से जुड़ा है। इसी मामले में हरियाणा सरकार के आठ विभागों से कथित तौर पर फर्जी तरीके से करीब 504 करोड़ रुपये निकाले गए थे। हरियाणा से जुड़े मामले में सीबीआई अब तक 37 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

दंगल मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास

कुंभड़ा में जल्द बनेगा खेल स्टेडियम: मेयर

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज़

मोहाली नगर निगम के मेयर सरबजीत सिंह समाणा ने कहा है कि गांव कुंभड़ा में जल्द ही खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा गांव में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल के दौरान की, जहां वे खिलाड़ियों और आयोजकों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे थे।

मेयर समाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्यभर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल स्टेडियमों के निर्माण का उद्देश्य युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्हें स्वस्थ रखना और उनकी खेल प्रतिभा



को आगे बढ़ाने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि कुंभड़ा में हर साल विशाल कुश्ती दंगल आयोजित किया जाता है और आयोजकों ने यहां स्थायी खेल स्टेडियम की मांग रखी है। इस मांग पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द यहां खेल स्टेडियम बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि भविष्य में खेल मेले और कुश्ती दंगल इसी स्थान पर आयोजित किए जा सकें।

समाणा ने कहा कि पंजाब सरकार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए

खेल आयोजनों को प्रोत्साहित कर रही है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इससे दूसरे युवाओं को भी खेलों में आगे आने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं को नशे से दूर रखने में भी मदद मिलती है और प्रदेश में सकारात्मक खेल माहौल तैयार हो रहा है। इस मौके पर डिप्टी मेयर हरपाल सिंह चन्ना, पार्षद नसीब सिंह रंधू, पुरजित सिंह सहित कई गणमान्य लोग और खेल आयोजक मौजूद रहे।

दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर माह 2,000 रुपये की मदद

■ अंडर-14 से अंडर-21 आयु वर्ग के पात्र खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, नियमित अभ्यास करने वालों पर फोकस
एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पात्र युवा खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहायता अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के उन खिलाड़ियों को दी जाएगी, जो दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियमों में नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को शुरूआती स्तर पर आर्थिक सहारा देकर नियमित अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुसार, छोटी उम्र में प्रशिक्षण,



Chief Minister

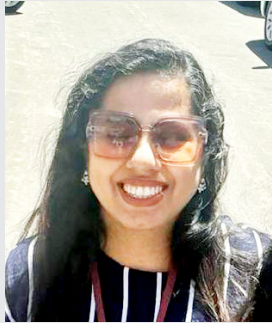
खेल सामग्री, पोषण और आने-जाने जैसी जरूरतों पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए चुनौती बनता है। मासिक सहायता से खिलाड़ियों को इन जरूरतों में कुछ राहत मिलने का उम्मीद है।

■ **प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर:** मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की युवा खेल प्रतिभाओं को

केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार सहयोग दिया जाएगा। सरकार पहले भी खेल प्रशिक्षण और संसाधनों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत राशि जारी कर चुकी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और संसाधनों के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

■ **जमीनी स्तर पर प्रतिभा तलाशने की कोशिश:** नई मासिक सहायता योजना को दिल्ली में खेल प्रतिभाओं की शुरुआती पहचान और उन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षण से जोड़े रखने की दिशा में कदम माना जा रहा है। सरकार का जोर ऐसे खिलाड़ियों को अवसर देने पर है, जिनमें क्षमता तो है, लेकिन आर्थिक कारणों से प्रशिक्षण जारी रखना कठिन होता है।

जब खामोशी बोल उठी : बानू मुश्ताक की ‘दिल का दीया’



समर न्यूज़ | चंडीगढ़

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका, अधिवक्ता और समाजसेविका बानू मुश्ताक का कहानी-संग्रह हार्ट लैप (मूल शीर्षक: हृदय दीप) केवल साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज की उन अनसुनी आवाजों का दस्तावेज है, जिन्हें अक्सर इतिहास और परिवार दोनों ही चुप करा देते हैं। इस संग्रह की कहानी 'दिल का दीया' स्त्री की पीड़ा, उसकी सहनशीलता और अंततः उसकी आत्म-अभिव्यक्ति की मार्मिक

कथा है। कहानी की नायिका महरून उन असंख्य स्त्रियों का चेहरा है, जो घर की चारदीवारी के भीतर अपनी इच्छाओं, सपनों और पहचान को धीरे-धीरे खो देती हैं। वह जीती तो है, लेकिन अपने लिए नहीं। उसका विवाह प्रेम और विश्वास से शुरू होता है, पर समय के साथ पति इनायत का अपनापन उपेक्षा में बदल जाता है। रिश्ते की गर्माहट खत्म हो जाती है और महरून का संसार भीतर ही भीतर बिखरने लगता है। जब इनायत उसे छोड़ने का निर्णय सुनाता है, तब महरून न कोई शिकायत करती है और न ही कोई शोर मचाती है। उसकी चुपची ही उसके टूटे हुए मन की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। यही मौन इस कहानी की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महरून हार मानने के बजाय स्वयं को खोजने का निर्णय लेती है। बचपन में शिक्षा से वंचित रही महरून धीरे-धीरे

पढ़ना-लिखना सीखती है और अपनी पीड़ा, स्मृतियों और अनुभवों को कागज पर उतारना शुरू करती है। उसकी कलम में साहित्यिक आडंबर नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई होती है। वही सच्चाई उसके शब्दों को असाधारण बना देती है। कुछ समय बाद उसकी बेटी सलमा माँ की डायरी पढ़ती है और समझती है कि यह केवल निजी अनुभव नहीं, बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों की कहानी है, जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। वह उस लेखन को 'दिल का दीया' नाम से प्रकाशित करवाती है। यह पुस्तक महरून की ही नहीं, हर उस स्त्री की आवाज बन जाती है, जिसने वर्षों तक चुप रहकर सब कुछ सहा है।

धीरे-धीरे यह कहानी अनेक महिलाओं को अपनी बात लिखने और कहने का साहस देती है। एक कोणी में जब सलमा अपनी माँ की कहानी पढ़ती है, तो सभा में बैठी कई महिलाएँ भावुक

होकर कह उठती हैं - "यह तो मेरी कहानी है।" कोई कहती है, "मैं भी महरून हूँ।" यही वह क्षण है जब एक स्त्री की निजी पीड़ा सामूहिक अनुभव में बदल जाती है। 'दिल का दीया' हमें याद दिलाती है कि स्त्री केवल परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने वाली नहीं, बल्कि संवेदनाओं, सपनों और आत्मसम्मान से भरा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उसकी खामोशी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब भी मौन शब्दों का रूप लेता है, तो वह केवल एक कहानी नहीं लिखता-वह बदलाव की शुरुआत करता है। बानू मुश्ताक की यह कहानी पाठकों को संवेदनशील बनाती है और यह विश्वास दिलाती है कि हर दबी हुई आवाज के भीतर एक ऐसा दीया जलता है, जो एक दिन स्वयं भी रोशनी बनता है और दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है।

पूजा सहगल
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय

जिला आयुष विभाग ने लगाया मेडिकल कैप

जगदीश लाल | नवांशहर

समर न्यूज़

जिला होम्योपैथी अधिकारी डॉ. राजीव जिंदिया की अगुवाई में गांव कमाप के वेल बस स्टैंड पर विशाल मेडिकल कैप का आयोजन किया गया। कैप का की उद्घाटन जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सरबजीत कौर द्वारा जेता किया गया। कैप में आयुर्वेदिक विभाग के डॉ. रजनीश कुमार और डॉ. ज्योति कठौर ने मरीजों का चेकअप कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां दीं। वहीं होम्योपैथी विभाग और द्वारा डॉ. हरदीप सिंह और डॉ. अमरिंदर सिंह ने मरीजों की जांच कर होम्योपैथिक दवाइयां प्रदान कीं।

फार्मासिस्ट हरजिंदर सिंह और इंद्रजीत कौर ने मरीजों को दवाइयां बांटीं। कैप में कुल 997 मरीजों की जांच की गई, जिनमें आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 632 और होम्योपैथी विभाग द्वारा 365 मरीज शामिल रहे।

पंजाब ग्रामीण बैंक ने अपना 22वां फाउंडेशन डे मनाया



जगदीश लाल | नवांशहर

समर न्यूज़

पंजाब ग्रामीण बैंक ने अपनी नवांशहर ब्रांच में अपना 22वां फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया। इस मौके पर, ब्रांच मैनेजर शोभित शर्मा और ब्रांच टीम ने कस्टमर्स से बातचीत की और उन्हें बैंक की अलग-अलग स्कीम्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने की इंटर्नेट से बारे में अवैयर किया।

यह प्रोग्राम रीजनल मैनेजर श्री अश्वनी दत्ता और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री राजेश मोहन भगत की

लीडरशिप में ऑर्गनाइज किया गया था। ब्रांच ने अपने कस्टमर्स हरमेश लाल, राज कुमार शर्मा, जगतार सिंह, मंगल सिंह और राकेश शर्मा ब्रांच टीम ने रीजन में कस्टमर-सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज देने और फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा देने का अपना कमिटमेंट दोहराया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मौनू के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं के तहत चार मामले दर्ज हैं, जबकि सचिन शुक्ला के खिलाफ 19 अप्रैल 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ था।

जेल से छूटे कथित तस्कर और अवैध हथियार समेत दबोचा

शुभम शर्मा | फिल्लौर

समर न्यूज़

गोराया पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में जेल से छूटकर आए एक व्यक्ति को कथित तौर पर अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, दो मैगजीन, चार कारतूस व 7.62 एएमएम के अन्य सामान की बरामदगी का दावा किया है।

थाना गोराया के प्रभारी परमिंदर सिंह शिंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जगतार सिंह उर्फ जा पुत्र तरसेम सिंह निवासी गांव फलपेटा के पास अवैध असला है। सूचना के आधार पर एएसआई सुरिंदर पाल ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए कथित आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति गांव में स्थित धन-धन बाबा सखता जी के धार्मिक स्थान पर ग्रंथी के तौर पर सेवा



भी करता है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी कट्टा, दो मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना गोराया में मुकदमा नंबर 202, थारा 25/27-54-59 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित तौर पर बरामद हथियार उसके पास कहां से आए और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और हथियार से जुड़े अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

कार की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

शुभम शर्मा | फिल्लौर

समर न्यूज़

फिल्लौर-गुराया हाईवे पर गांव बच्छोवाल के सामने शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर खड़े एक टिप्पर में पीछे से एक कार जा टकराई। हादसे में कार सवार करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि कार चालक भी घायल हो गया।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने दोनों घायलों को प्राथमिक सहायता देने के बाद उपचार के लिए सिविल अस्पताल फिल्लौर पहुंचाया।

इस संबंध में सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज एएसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि गांव बच्छोवाल के सामने हाईवे पर एक टिप्पर खड़ा था। टिप्पर चालक उसमें पानी डाल रहा था। इसी दौरान जालंधर की ओर से आ रही कार अनियंत्रित होकर टिप्पर के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार

फेज-7 मार्केट में जगह-जगह कूड़े के ढेर पार्षद काहलों ने उठाए सवाल

गुरशरण सिंह | मोहाली

समर न्यूज़

नगर निगम के पार्षद परमजीत सिंह काहलों ने फेज-7 मार्केट में सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई ठेकेदार की ओर से जरूरी प्रबंध नहीं किए जाने के कारण मार्केट में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे दुकानदारों और खरीदारों के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

काहलों ने कहा कि मार्केट के दुकानदारों ने कई बार नगर निगम की सफाई शाखा तक पहुंचकर व्यवस्था सुधारने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने मार्केट की सफाई का काम ठेके पर दिया हुआ है, लेकिन संबधित ठेकेदार की ओर से न तो नियमित और उचित तरीके से सफाई करवाई जा रही है और न ही समय पर कूड़ेदानों से



कचरा उठाया जा रहा है। काहलों के अनुसार, इसी लापरवाही का नतीजा है कि मार्केट के कई हिस्सों में कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। इससे न केवल गंदगी फैल रही है, बल्कि दुर्गंध और अस्वच्छ माहौल के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है।

उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मांग की कि सफाई व्यवस्था की तुरंत समीक्षा की जाए और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मार्केट के नियमित सफाई और समय पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि दुकानदारों और आम लोगों को राहत मिल सके।

फैक्टरी में काम करने को कहने पर अधिकारी पर दोस्तों से करवाया हमला दो हमलावर काबू, मोबाइल से फैक्टरी कर्मचारी के साथ चैट मिलने का दावा

गुरमीत सिंह | डेराबस्सी

समर न्यूज़

मुबारकपुर रोड स्थित एलेंजर फैक्टरी में काम करने वाले एक कर्मचारी द्वारा अपने ही अधिकारी पर दोस्तों के जरिए हमला करवाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे अन्य फैक्टरी कर्मचारियों ने दोनों हमलावर युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

फैक्टरी के मेटेनेंस विभाग में अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि वह सुबह मोटरसाइकिल से डेराबस्सी से फैक्टरी की ओर जा रहे थे। जब वह डीएवी स्कूल के पास पहुंचे तो दो युवकों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अन्य फैक्टरी कर्मचारियों ने मौके



पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और दोनों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने कथित तौर पर बताया कि उन्हें फैक्टरी में काम करने वाले कुलदीप नामक कर्मचारी ने महेंद्र शर्मा पर हमला करने के लिए भेजा था।

पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों के मोबाइल फोन की जांच के दौरान उनके और फैक्टरी कर्मचारी के बीच हुई चैट भी मिलने का दावा किया गया है। महेंद्र शर्मा के अनुसार, कुलदीप सिंह काम में लापरवाही

बरतता था। इसी कारण उसे कई बार काम को लेकर समझाया गया था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर कुलदीप ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के माध्यम से उन पर हमला करवाने की योजना बनाई।

बताया गया है कि हमला करवाने वाला कर्मचारी घटना के समय रोजाना की तरह ड्यूटी पर आयु हुआ था। जब उसे दोनों युवकों के पकड़े जाने की जानकारी मिली तो वह मौका पाकर फैक्टरी से फरार हो गया। दोनों युवकों को मुबारकपुर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया गया है। चौकी प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बरामद किए गए मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पकड़े गए युवकों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है।

शहरी जिला कांग्रेस कमेटी ने मंत्री चीमा के खिलाफ सौंपा मांगपत्र



दलजीत वित्की | लुधियाना

समर न्यूज़

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से गुलजार सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप के तहत जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी), लुधियाना की ओर से संजय तलवाड़ (पूर्व विधायक), अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) के नेतृत्व में सुरेंद्र डाबर, कुलदीप सिंह वैद, सिमरजीत सिंह बैस, बलविंदर सिंह बैस, विपिन अरोड़ा, सरबजीत सिंह सरहाली, संजीव कुमार शर्मा, हरमिंदर सिंह (मोनू खिंडा), गुरप्रीत सिंह (गोपि), ललित मेहरा (लक्की), तलविंदर सिंह (टोनी), बलजीत सिंह (मान), दविंदर सिंह बांसल,

लखबीर सिंह टोना सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री की बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर मांग-पत्र सौंपा।यह मांग-पत्र रूपिंदर सिंह, सहायक पुलिस कमिश्नर, लुधियाना के माध्यम से पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नाम सौंपा गया।

इसमें दलित गुलजार सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में वित्त मंत्री हरपाल चीमा के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई।मांग-पत्र में दिड़बा के निवासी दलित गुलजार सिंह की तरफ से की गई आत्महत्या का हवाला दिया गया, जिसने चीमा और उनके समर्थकों द्वारा धमकाने के बाद यह कदम उठाया था।

138 वोट लेकर अजय कुमार बने फिल्लौर बार काउंसिल के अध्यक्ष



शुभम शर्मा | फिल्लौर

समर न्यूज़

स्थानीय बार काउंसिल के चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। कुल 245 वोट डाले गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए कड़े मुकाबले में अजय कुमार ने 138 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी दिनेश कमल को 105 वोट मिले।

इस तरह अजय कुमार ने 33 वोटों के अंतर से अध्यक्ष पद अपने नाम किया। चुनाव परिणाम सामने आते ही विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अलग-अलग पदों के लिए हुए मुकाबलों में कई उम्मीदवारों ने स्पष्ट अंतर से जीत दर्ज की, जबकि अध्यक्ष पद का मुकाबला बेहद

कांटे का रहा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए श्री सुरजीत राम खेतान ने 142 वोट हासिल किए। उन्होंने श्री चेतन अग्रवाल को 45 वोटों के अंतर से पराजित किया, जिन्हें 97 वोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट पद पर सुश्री रिंतु सेनी ने 123 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने सुश्री परमजीत को 116 वोट मिले और मुकाबला 7 वोटों से अपने नाम किया।

सचिव पद पर अकाशदीप अग्निहोत्री ने 148 वोट प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने श्री जसविंदर सिंह को 50 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 98 वोट मिले। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर श्री बलदीप कुमार ने 167 वोट हासिल किए और श्री बलदेव राज को 93 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया।

बदलते मूल्य, बदलती पीढ़ी: जेन-जी को समझने की कोशिश

अक्सर वरिष्ठों से यह सुनने को मिलता है कि आज की युवा पीढ़ी में पहले जैसे संस्कार और मूल्य नहीं रहे। विशेषकर 1997 के बाद जन्मी पीढ़ी, जिसे जेन-जी कहा जाता है, को लेकर यह धारणा और मजबूत है। लेकिन इसे मूल्यों का ह्रास कहना उचित नहीं होगा; यह अधिक सही है कि यह मूल्य-व्यवस्था में बदलाव (शिफ्ट इन वैल्यूज) है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण तकनीक का व्यापक प्रभाव है। जेन-जी वह पहली पीढ़ी है जिसने तकनीक को बाहरी साधन नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना है।

हमारी पीढ़ी के बचपन में सीमित मोबाइल और धीरे-धीरे आते कंप्यूटर थे, जबकि जेन-जी ने स्मार्टफोन, इंटरनेट और

सोशल मीडिया के बीच आंखें खोलीं। कई बच्चों के लिए मोबाइल एक तरह का डिजिटल बेबीसिटर बन गया। इसका असर केवल बच्चों पर पड़ा। माता-पिता करियर और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे, वहीं दादा-दादी भी तकनीक से जुड़ गए। परिणामस्वरूप पीढ़ियों के बीच वह संवाद कम हो गया जिसमें मूल्य स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित होते थे।

पहले बच्चे परिवार के व्यवहार से सीखते थे-बड़ों का सम्मान, मेहमाननवाजी और सामाजिक संवेदनशीलता। आज यह सीख केवल घर तक सीमित नहीं रही; इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्मों और डिजिटल दुनिया से भी प्रभावित होती है। इसलिए जेन-



जी को यह कहकर खारिज करना कि उनमें संस्कार नहीं हैं, सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि उनके मूल्य किस वातावरण में विकसित हो रहे हैं।

आज की पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानसिक स्वास्थ्य, सामनता और वकै लाइफ बैलेंस को अधिक महत्व देती है और परंपराओं पर सवाल भी उठाती

है। यह सवाल करना हमेशा असम्मान नहीं होता, बल्कि सोच का विस्तार भी हो सकता है। अंतर केवल संवाद के तरीके का है।

हर पीढ़ी अपने समय की परिस्थितियों का परिणाम होती है। पुरानी पीढ़ी ने सीमित संसाधनों में धैर्य और सामूहिकता सीखी, जबकि जेन जी तेज तकनीकी बदलाव और वैश्विक संपर्क के बीच विकसित हुईं। दोनों की चुनौतियां अलग हैं।

जेन जी में कई सकारात्मक मूल्य भी मजबूत हैं-जैसे लैंगिक समानता, पर्यावरण जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता। साथ ही, स्त्रीन पर अधिक समय, तुलना की प्रवृत्ति और त्वरित परिणाम की अपेक्षा जैसी

चुनौतियां भी हैं। समाधान आरोप नहीं, संवाद है। मूल्य उपदेश से नहीं, उदाहरण से सीखते हैं। यदि हम सम्मान चाहते हैं, तो उसे व्यवहार में दिखाना होगा।

अंततः, मूल्य समाप्त नहीं होते, वे समय के साथ रूप बदलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम मानवता, ईमानदारी और करुणा जैसे मूल्यों को बनाए रखें और साथ ही स्वतंत्रता व समानता जैसे नए मूल्यों को भी स्वीकार करें। संवाद यह नहीं कि आज की पीढ़ी में मूल्य हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कौन से मूल्य देकर जा रहे हैं - क्योंकि वे वही सीखेंगे जो वे हमें करते हुए देखेंगे।

सुश्री सविता शर्मा
सहायक प्राध्यापक
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय

नशे के खिलाफ जंग को गांव-वार्ड स्तर तक पहुंचाने की तैयारी तेज

शुभम शर्मा | फिल्लौर

समर न्यूज़

पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लौर में कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष एक्शन टैकिंग रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई।

बैठक में गांवों और वार्डों तक पहुंच बनाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा अभियान की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान को केवल सरकारी स्तर तक सीमित रखने के बजाय इसे गांव और वार्ड स्तर तक जन-अभियान का रूप देना रहा। अधिकारियों को निर्देशित



किया गया कि जागरूकता कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नशे के खिलाफ मुहिम से जोड़ा जा सके।

बैठक में गांव/वार्ड स्तर पर जागरूकता बैठकें आयोजित करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जागरूकता बैठकों के आयोजन, लोगों के साथ संवाद तथा अभियान के संदेश को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग

शुभम शर्मा | फिल्लौर

समर न्यूज़

नशों की अवैध सप्लाई और बिक्री पर रोक लगाने के लिए स. हरविंदर सिंह विरक, एसएसपी जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के अनुसार जालंधर ग्रामीण पुलिस ड्राग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ऑपरेशन चलाए गए। इन अभियानों के दौरान पुलिस टीमों द्वारा नशों से संबंधित गतिविधियों के लिए चिन्हित संदिग्ध स्थानों की जांच के लिए की गई।

संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन, वाहनों की चेकिंग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी को भी सुनिश्चित किया गया। यह अभियान संबंधित सब-डिवीजनों के डीएसपी की निगरानी में चलाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर चेकिंग अभियान का जायजा लिया गया तथा पुलिस टीमों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू



करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान चिह्नित नशा हॉटस्पॉट्स के अलावा खाली मकानों, सुनसान स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों को विशेष रूप से कवर किया गया। इन स्थानों की गहन तलाशी और चेकिंग की गई। इस विशेष अभियान के दौरान जालंधर ग्रामीण के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 एफआईआर दर्ज की गईं और इन मामलों में 4 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

